भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-220

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक

†*220. **मोहम्मद रकीबुल हुसैन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक (पीजीआई) 2.0 की दूसरी निम्नतम श्रेणी में रखा गया था;
(ख) असम के खराब प्रदर्शन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने असम में स्कूली शिक्षकों की भारी कमी और शिक्षण पर इसके परिणामों तथा उन्हें विद्यालय में बनाए रखने पर इसके प्रभाव का संज्ञान लिया है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संरचनात्मक कमी को दूर करने और भावी पीजीआई मूल्यांकन में असम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा 'प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक' के संबंध में दिनांक 04/08/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 220 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर स्कूल शिक्षा के प्रमुख प्रेरक प्रदर्शन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मापने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 73-संकेतक आधारित प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 तैयार किया है। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए पीजीआई 2.0 संयुक्त रिपोर्ट में असम सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र-वार प्रदर्शन को https://spgi.udiseplus.gov.in पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, असम ने वर्ष 2023-24 के लिए पीजीआई 2.0 में अकांशी-2 ग्रेड प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य का समग्र प्राप्तांक वर्ष 2022-23 के 498.8 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 511.5 हो गया है जो प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर प्रगति और विकास को दर्शाता है।

(ग) और (घ): निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) मानदंड क्रमशः 30:1 और 35:1 हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 2.4 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि "प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 30:1 से कम का छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) सुनिश्चित किया जाएगा; जिन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की संख्या अधिक है, वहाँ 25:1 से कम पीटीआर का लक्ष्य रखा जाएगा।"

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा प्लस (यूडाईज़+) के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली विकसित की है। यूडाइज+ 2023-24 के अनुसार, असम राज्य में शिक्षा के स्तर के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निम्नानुसार है:

राज्य	शिक्षा के स्तर के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर)			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
असम	19	13	11	18

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक

स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत छात्रावासों का निर्माण, असंतृप्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छात्रावासों का निर्माण, निःशुल्क यूनीफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल है।

'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है जिसमें बालवाटिका शामिल है।

इसके अलावा, पीएम श्री योजना के तहत, असम राज्य के 382 पीएम श्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने हेतु उन्नयन के लिए चुना गया है। ये स्कूल संज्ञानात्मक विकास और 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से युक्त समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह योजना एक समतामूलक, समावेशी और आनंदमय शिक्षण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं को पूरा करता है। ये स्कूल छात्रों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक बच्चा एक सुरक्षित और प्रेरक वातावरण में स्वागत, देखभाल और समर्थन किया हुआ महसूस करे।

इसके अलावा, असम राज्य सरकार ने व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और राज्य के शैक्षिक प्रदर्शन को और मज़बूत करने के लिए विभिन्न पहल और केंद्रित मध्यवर्तन किए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं

- एक संरचित एनईपी 2020- पहल के तहत, वर्ष 2024-25 में 1.35 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 1.29 लाख शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से एफएलएन, शिक्षाशास्त्र, ध्वनिविज्ञान, सुलेख और टीएलएम उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया गया था। इसी प्रकार, आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय और एनआईटी सिलचर जैसे संस्थानों के सहयोग से माध्यमिक शिक्षकों को भी विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया - जो शिक्षक के विकास के लिए राज्य के सबसे बड़े प्रयासों में से एक है।
- असम ने वास्तविक समय शिक्षा शासन के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'शिक्षा सेतु एक्सोम' का संचालन किया है। यह छात्र और शिक्षक की उपस्थिति, मूलभूत

संरचना की स्थिति आदि सहित प्रमुख स्कूल-स्तरीय संकेतकों की स्वचालित ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।

- कक्षा 3-5 में अधिगम के अंतराल को कम करने के लिए, असम 'सही स्तर पर शिक्षण (टीएआरएल)' पहल को कार्यान्वित कर रहा है, जो कक्षा-आधारित से अधिगम-स्तर-आधारित शिक्षण में स्थानांतरित हो रहा है।

- असम ने स्थानीय कार्यान्वयन के लिए एसपीएमयू और डीपीएमयू के साथ बहुस्तरीय एफएलएन कार्यनीति अपनाई। एनसीएफ-एफएस के अनुरूप, पाठ्यपुस्तकें और कार्यपुस्तिकाएँ विकसित की गईं और छात्रों को 16 संख्यात्मक शिक्षण सामग्री (टीएलएम) प्रदान की गईं। स्कूलों को शिक्षण सुदृढ़ बनाने के लिए 12 अतिरिक्त टीएलएम और साक्षरता किट प्रदान की गईं, जिनमें बड़ी किताबें, चार्ट, फ़्लैशकार्ड और गतिविधि पुस्तकें शामिल थीं।
- असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं और टेली-एजुकेशन सुविधाओं के माध्यम से डिजिटल लर्निंग का विस्तार किया है। स्मार्ट कक्षा-वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए ई-सामग्री विकसित और प्रसारित की गई है। 'मिशन ज्ञान' और 'ई-कक्षा ऐप' के साथ साझेदारी के माध्यम से, स्कूल स्तर पर सामग्री सुलभ बनाई गई है। टेली-कक्षा अवसंरचना के माध्यम से स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में लाइव 2 डी/3 डी टेली-कक्षाएं प्रसारित की जाती हैं।

*****